हम एक वायरस से युद्ध लड़ रहे हैं. मैं इससे निपटने के लिए तीन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण मानता हूँ: पहला- स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति से निपटना. दूसरा, हमें इसके सामाजिक प्रभाव और आर्थिक उपाय तथा इसमें अच्छे सुधार पर ध्यान देना होगा. तीसरा, और अंततः एक 'बेहतर स्थिति' में पहुंचना हमारा उत्तरदायित्व है. हमें सामूहिक रूप से इस संकट से पार पाने के लिए पहले से कहीं अधिक एकजुटता, आशा और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है.

— एंटोनियो गुटेरेस [1]

1

चुनौतियों का वर्ष

2020 की शुरूआत में विश्व को अपनी चपेट में लेने वाली इस कोविड-19 महामारी ने तब से अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रखा है. यह अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट वैश्विक स्तर पर मानव जीवन और आजीविका को रूपांतरित होने के लिए बाध्य कर रहा है. इस बीच, वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, भारतीय कृषि 3.6% की दर से बढ़ी है - जबकि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र संकुचित हुए हैं.[2]

हम भी, नाबार्ड में इस प्रतिकूलता को दृढ़ता से पार करते हुए वित्तीय वर्ष 2021 में अपने तुलनपत्र के आकार में रिकार्ड 23.6% की वृद्धि के साथ ₹6.6 लाख करोड़ के निकट पहुंच गए हैं (अध्याय 9). यद्यपि वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान हमारे परिचालनों और कार्यनिष्पादन का विस्तृत विवरण अनुवर्ती अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है, इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2021 की प्रमुख गतिविधियों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है जिनका हम पर प्रभाव पड़ा है.

1.1 'जीवन और आजीविका' के मध्य दुविधा

महामारी ने इस कठिन समय में, विशेष रूप से देश के आकार और जटिलता को देखते हुए भारत के सामने अत्यंत विकट विकल्प उपस्थित कर दिया. दीर्घकालिक लाभ की आशा रखते हुए कुछ अल्पकालिक दर्द सहकर भारत ने कड़े राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लागू किया. इस वजह से आर्थिक गतिविधियों में उत्पन्न अत्यधिक व्यवधान से निर्धन और कमजोर लोगों के साथ-साथ व्यावसायिक क्षेत्र (विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम या एमएसएमई) ने नुकसान उठाया.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने इन क्षेत्रों के समक्ष उपस्थित आर्थिक कठिनाई को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई; जन-धन खाते रखने वाली विधवाओं, पेंशनभोगियों और महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से

सहायता दी गई; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त निधि मंजूर की गई और व्यवसायों के लिए ऋण-स्थगन और चलनिधि सुविधा प्रदान की गई. वित्तीय वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में आवागमन और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों में ढील के बाद सरकार ने निवेश और उपभोग की मांग को प्रोत्साहित करने, विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) 2.0 और 3.0 नामक सुविचारित योजना शुरू की.

1.2 गंभीर वित्तीय संकुचन

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष[3] और विश्व बैंक[4] के अनुसार महामारी के कारण 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.5%–4.3% का संकुचन आया. मांग में दबाव और आपूर्ति में व्यवधान के परिणामस्वरूप फिक्स्ड निवेश, निजी उपभोग और निर्यात में संकुचन आ गया.

मार्च-मई 2020 के दौरान लगाए गए कड़े लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से संकुचन हुआ. इससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वित्तीय वर्ष 2021 की पहली तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई और इसके बाद की तिमाही में 7.5% की कमी दर्ज की गई.[5] लंबे समय से जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, सामाजिक दूरी के मानदंडों और प्रवासी श्रमिकों के बड़े पैमाने पर पलायन के कारण विनिर्माण, निर्माण, व्यापार और परिवहन क्षेत्रों में भारी गिरावट आ गई. ऋण की स्थिति भी सुस्त बनी रही.

हालांकि, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत कई पैकेजों की घोषणा के साथ वित्तीय वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में आर्थिक गतिविधियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया (बॉक्स 1.1). वित्तीय वर्ष 2021 के राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 0.4% और चौथी तिमाही में 1.6% होने का संकेत मिला और इस प्रकार पूरे वित्तीय वर्ष 2021 के लिए वास्तविक जीडीपी का संकुचन 7.3% रहा.[6]

बॉक्स 1.1: आर्थिक सुधार के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज

> हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा. आत्मनिर्भर भारत के उत्कृष्ट भवन का निर्माण अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकी और मांग के पाँच आधार स्तंभों पर होगा.
>
> – भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

यह सरकार राष्ट्र सर्वप्रथम; किसानों की आय दोगुना करना; मजबूत आधारभूत संरचना; स्वस्थ भारत; सुशासन; युवाओं के लिए अवसर; सभी के लिए शिक्षा; महिलाओं का सशक्तीकरण और समावेशी विकास पर बल देते हुए आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) के निर्माण के माध्यम से महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से सीधे निपटने की तैयारी में है.

एएनबी 1.0 पैकेज का उद्देश्य सुधार प्रक्रिया को जारी रखना था, जबकि एएनबी 2.0 और एएनबी 3.0 पैकेजों का लक्ष्य विकास की गति को और तेज करना था. वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान तीनों एएनबी पैकेजों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपायों के लिए जीडीपी के 15.7% के कुल वित्तीय परिव्यय का अनुमान लगाया गया था.*

* आरबीआई (2021), *वार्षिक रिपोर्ट 2020-21*, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई.

1.3 मुद्रास्फीति का लक्ष्य चूक गया

आपूर्ति श्रृंखला में उत्पन्न व्यवधानों के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति अप्रैल 2020 से लगातार आठ महीने के दौरान 6% के स्वीकार्य स्तर के ऊपर बनी रही. अनुकूल आधार प्रभाव और प्रमुख सब्जियों की कीमतों में तेज गिरावट से सीपीआई मुद्रास्फीति हेडलाइन दिसंबर 2020 से 6% के नीचे आ गई (चित्र 1.1). यद्यपि सीपीआई मुद्रास्फीति दिसंबर 2020–मार्च 2021 के दौरान लक्ष्य (4±2%) के दायरे में रही, लेकिन आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों और बढ़ती निविष्टि लागतों के कारण ऊपर की ओर दबाव बना रहा. आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयास से आगामी महीनों में मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिल सकती है, बशर्ते महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों में कमी आए.

चित्र 1.1: मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक

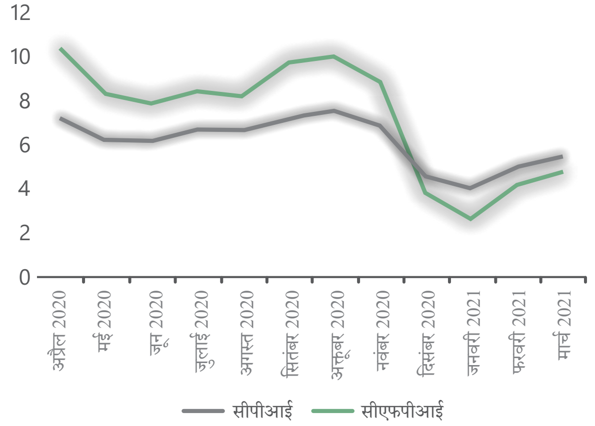

नोट: सीपीआई = उपभोक्ता मूल्य सूचकांक; सीएफ़पीआई = उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार www.mospi.nic.in.

1.4 रिकार्ड कृषि उत्पादन

रबी फसलों की कटाई के समय ही अचानक देशव्यापी 'कोविड-लॉकडाउन' लगने से कृषि निविष्टियों और मशीनरी की आवाजाही में बाधा उत्पन्न हो गई. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में

जाकर कृषि का मौसमी कार्य करने वाले श्रमिकों की आवाजाही रूक गई और इसके परिणामस्वरूप संबन्धित गंतव्य राज्यों में मजदूरों की कमी हो गई और उनके अपने मूल राज्यों में भूमि पर दबाव बढ़ गया; कई मजदूर बिना कमाई के बंद शहरों में फंस गए. इन बाधाओं के बावजूद, खाद्यान्न आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई. इसका श्रेय भारतीय किसानों और खाद्य आपूर्ति शृंखला से जुड़े अन्य हितधारकों को जाता है. इसके परिणामस्वरूप, कृषि और अनुषंगी क्षेत्र के सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में स्थिर कीमतों (2011-12 शृंखला) पर 3.6% की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई (चित्र 1.2).[7]

चित्र 1.2: स्थिर कीमतों पर जीवीए की वृद्धि दर(%) का रुझान (2011-12 शृंखला)

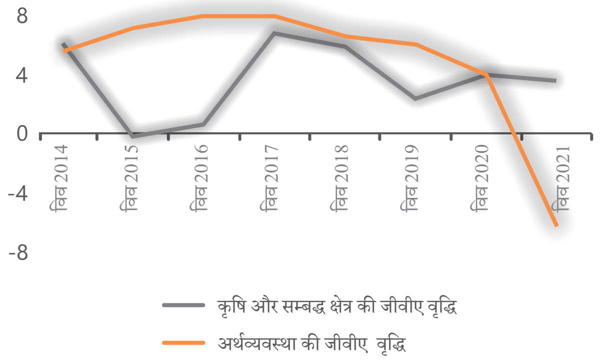

नोट: जीवीए = सकल वर्धित मूल्य

स्रोत: जीओआई (2021), 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.

एक तरह से, कोविड-19 महामारी ने कृषि क्षेत्र को भारत के विकास में एक उत्प्रेरक शक्ति बनने का अवसर दिया. भारतीय किसानों ने वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में खरीफ मौसम के बुवाई क्षेत्र में 5.7% और रबी मौसम में 4.3% की वृद्धि की है. इसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2021 में खाद्यान्न उत्पादन 305.4 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर

चित्र 1.3: कृषि उत्पादन

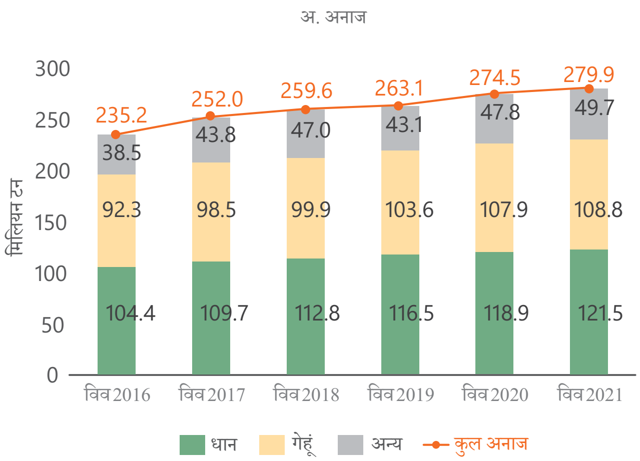

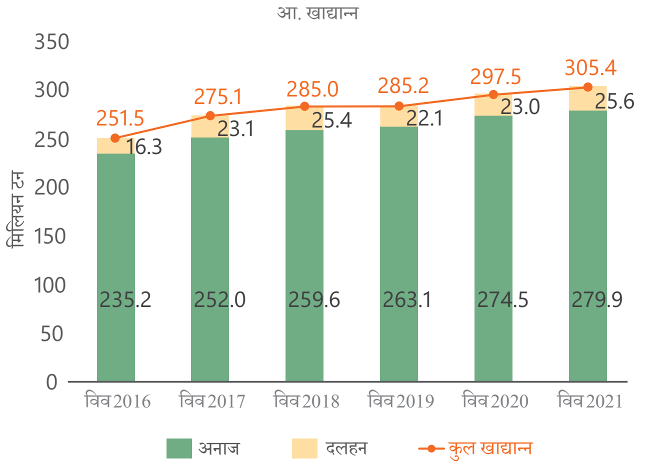

नोट: पूर्णांकित किए जाने के कारण कारकों को कुल में नहीं जोड़ा जा सका.

स्रोत: जीओआई (2021), खाद्यान्न के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान (चित्र 1.3अ और आ के लिए) और तिलहन और वाणिज्यिक फसलों (चित्र 1.3इ के लिए) के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

पर पहुँच गया, जो पिछले वर्ष से 8 मिलियन टन अधिक है. कुल खाद्यान्न उत्पादन वित्तीय वर्ष 2016 और वित्तीय 2020 के बीच के औसत उत्पादन से 26.6 मिलियन टन अधिक रहा (चित्र 1.3 अ और आ).[8]

वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में, तीन प्रमुख वाणिज्यिक फ़सलों-तिलहन (10%), गन्ना (6%) और कपास (1.1%) का उत्पादन बढ़ गया (चित्र 1.3 ग). औषधीय और सुगंधित पौधों (10.6%) और सब्जियों (2.5%) के उत्पादन में वृद्धि सभी बागवानी उत्पादों में सबसे अधिक (326.6 मिलियन टन अनुमानित) थी (तालिका 1.1).

तालिका 1.1: बागबानी फसलें - क्षेत्रफल और उत्पादन

	क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)			*उत्पादन (मिलियन टन)*		
	वित्तीय वर्ष 2019	*वित्तीय वर्ष 2020*	*वित्तीय वर्ष 2021*	*वित्तीय वर्ष 2019*	*वित्तीय वर्ष 2020*	*वित्तीय वर्ष 2021*
फल	66.0	67.6	69.6	98.0	102.0	103.2
सब्जियां	100.7	103.0	107.1	183.2	188.9	193.6
टमाटर	*7.8*	*8.1*	*8.3*	*19.0*	*21.2*	*20.1*
प्याज	*12.2*	*14.3*	*16.0*	*22.8*	*26.1*	*26.3*
आलू	*21.7*	*20.5*	*22.5*	*50.2*	*48.6*	*53.1*
सुगंधित एवं औषधीय पौधे	6.3	6.4	6.5	0.8	0.7	0.8
फूल	3.0	3.2	3.2	2.9	3.0	2.8
शहद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.1	0.1	0.1
बागान फसलें	40.7	40.8	41.1	16.6	15.7	15.8
मसाले	40.7	43.5	44.1	9.5	10.3	10.2

स्रोत: जीओआई (2021), 2020-21 के लिए बागबानी फसलों का क्षेत्र और उत्पादन (पहला अग्रिम अनुमान), राष्ट्रीय बागबानी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

चित्र 1.4: आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सम्बद्ध क्षेत्र के लिए पहलें

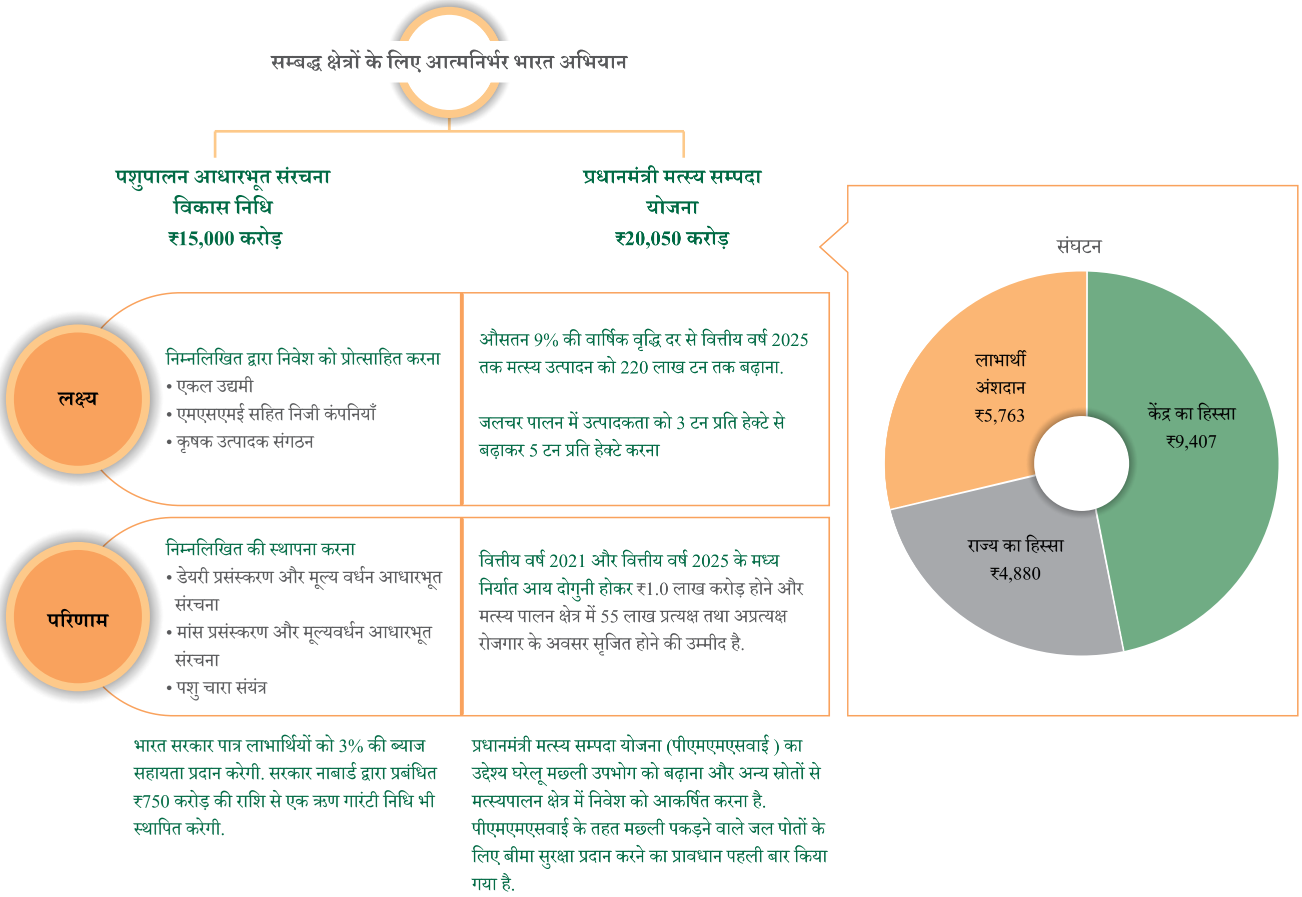

नोट: 1. एमएसएमई = सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम.
2. पीएमएमएसवाई के घटक ₹ करोड़ में हैं.
3. पीएमएमएसवाई में लाभार्थियों का अंशदान केवल वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2025 तक.

स्रोत: जीओआई (2020), आत्मनिर्भर भारत पैकेज – भाग 3, पत्र सूचना कार्यालय, दिनांक 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति. https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/Aatma%20Nirbhar%20Bharat%20Presentation%20Part-3%20Agriculture%2015-5-2020%20revised.pdf.

1.5 संबद्ध क्षेत्र का अच्छा प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2015 और वित्तीय वर्ष 2019 के बीच 8.2% चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ते हुए, पशुधन क्षेत्र ने सकल वर्धित मूल्य (जीवीए) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान को 24.3% से बढ़ाकर 28.6% (स्थिर कीमतों पर) कर दिया. वित्तीय वर्ष 2019 के लिए कुल जीवीए में इसका योगदान 4.2% रहा.[9]

भारत ने वित्तीय वर्ष 2020 में 14.2 मिलियन टन मछली का उत्पादन किया, जो विश्व स्तर पर 7.6% की हिस्सेदारी के साथ दूसरा सबसे अधिक उत्पादन है. यह क्षेत्र कुल जीवीए में 1.2% और कृषि जीवीए में 7.3% का योगदान देता है. देश ने वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान ₹46,662 करोड़ मूल्य के 1.3 मिलियन टन समुद्री उत्पाद का निर्यात किया. मछली उत्पादन ने 28 मिलियन से अधिक भारतीयों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान दिया है, इसमें से अधिकतर सीमांत और कमजोर समुदायों से आते हैं जो आजीविका के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं.[10] आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत संबद्ध गतिविधियों के लिए उठाए गए कदमों का विवरण चित्र 1.4 में प्रस्तुत है.

1.6 उत्कृष्ट कृषि निर्यात

भारत के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 में लगभग 38 बिलियन डॉलर पर रुक गया था और वित्तीय वर्ष 2020 में 35.2 बिलियन डॉलर तक कम होने के बाद वित्तीय वर्ष 2021[11] में 17.3% से 41.3 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया. यद्यपि भारत समुद्री उत्पादों, बासमती चावल, भैंस के मांस, मसाले, गैर-बासमती चावल, कच्चे कपास, ऑइल मिल, चीनी, अरंडी का तेल और चाय के वैश्विक व्यापार में अग्रणी है, लेकिन वैश्विक कृषि व्यापार में इसका हिस्सा 2.5% से थोड़ा ही अधिक है (चित्र 1.5).[12]

भारत दुनिया में चावल, विशेष रूप से गैर-बासमती चावल के सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है, इसका कारण कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान चावल को स्टॉक करने की यूरोपीय देशों के परिवारों से मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग से प्रेरित है. वियतनाम और थाईलैंड सहित अन्य प्रमुख निर्यातकों के समक्ष उपस्थित आपूर्ति व्यवधानों से भी भारतीय निर्यात को लाभ मिला है.

1.7 कृषि ऋण में दो अंकों की वृद्धि

भारतीय कृषि क्षेत्र में पूंजी की कमी से जूझ रहे मुख्यतः छोटे भूमिधारक हैं, जिनके लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है. केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और वित्तीय संस्थानों ने कृषि के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह को निरंतर विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वित्तीय वर्ष 2021 में ₹15.0 लाख करोड़ के लक्ष्य के समक्ष 31 मार्च 2021 तक ₹15.6 लाख करोड़ के कृषि ऋण संवितरित किए गए.[13] इस गति को बनाए रखने के लिए केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए यह लक्ष्य ₹16.5 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है.

किफायती ऋण तक पहुंच सुलभ होने से किसानों के लिए नई तकनीक, कृषि मशीनीकरण और वाणिज्यीकरण को अपनाने का रास्ता आसान होगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी. लेकिन, हमें ऋण आपूर्ति बढ़ाने से आगे जाकर आधारभूत संरचना के निर्माण, वित्तीय स्थिति में सुधार, कृषि-प्रौद्योगिकी और किसानों की डिजिटल साक्षरता में सुधार लाकर किसानों की ऋण अवशोषण क्षमता के विस्तार के माध्यम से मांग को बढ़ाने पर ज़ोर देना चाहिए और कृषि निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए.

चित्र 1.5: कृषि निर्यात का संक्षिप्त ब्यौरा

स्रोत: 1. पीआईबी (2021): भारत ने 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात में उत्कृष्ट वृद्धि दर्ज की, पत्र सूचना कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 10 जून. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1725891.

2. जीओआई (2021), आर्थिक सर्वेक्षण 2021-21, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

मई 2020 में, एएनबी पैकेज के तहत कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ तक की चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए 11 उपायों - तीन सुधारों और आठ पहलों की घोषणा की गई (सुधारों के लिए बॉक्स 1.2 देखें).

बॉक्स 1.2: आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत घोषित कृषि सुधार 2020

1. ऐसी आशा है कि **कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण), अधिनियम 2020** के अंतर्गत खुले व्यापार, क्रेताओं के मध्य प्रतिस्पर्धा की वृद्धि होगी, अंतर-राज्यीय व्यापार बाधाओं को हटाने और किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे और इस प्रकार किसानों की आय बढ़ेगी. ऐसी उम्मीद है कि एपीएमसी के कार्यक्षेत्र को अलग कर देने के उपरांत एपीएमसी मार्केट यार्ड से बाहर व्यापार करने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
2. **कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020** का लक्ष्य बुवाई के समय किसानों को कीमत का आश्वासन देना है. वायदा संविदाओं (अर्थात् कारपोरेट निकायों के साथ) पर आधारित फसल उगाने के निर्णयों से बाज़ार जोखिम कम होगा और खाद्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में अनिश्चितता की समस्या का हल निकल सकेगा.
3. **आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020** का लक्ष्य कृषि आपूर्ति शृंखला, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और निर्यात आधारभूत संरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है.

ऐसी उम्मीद है कि समग्र रूप से इन सुधारों से किसानों को संगठित कृषि व्यवसाय घरानों तक सीधी पहुँच मिल सकेगी और इसके परिणामस्वरूप कृषि व्यवसाय निकायों को बैकवर्ड इंटीग्रेशन की सुविधा मिलने में आसानी होगी. इससे एक सुदृढ़ और कार्यशील मूल्य शृंखला के निर्माण के लिए कृषि आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, प्रणालीगत पारदर्शिता और कृषि आधारभूत संरचना के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.

नोट: एपीएमसी = कृषि उत्पाद विपणन समिति

मार्च 2020 के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के मद्देनजर मौद्रिक नीति को आसान बनाने के लिए कई परंपरागत और गैर परंपरागत उपाय किए (चित्र 1.6).

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान उद्योग (0.4%) और सेवा (1.4%) की तुलना में कृषि में सकल बैंक ऋण बकाया (26 मार्च 2021 की स्थिति में) में 12.3% की उच्चतम वर्ष-दर-वर्ष बढ़ोतरी देखी गई.[14] वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान नाबार्ड के ऋण और अग्रिम में 25.2% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 11.5% थी. यह उत्साहवर्धक है कि इसका आधा हिस्सा उत्पादन और

चित्र 1.6: महामारी के मद्देनजर भारतीय रिज़र्व बैंक की पहल

परंपरागत उपाय	गैर परंपरागत उपाय
• नीतिगत रेपो दर में 115 बेसिस पॉइंट की कमी • नकदी प्रारक्षित निधि अनुपात में 100 बेसिस पॉइंट की कमी	• पुनर्वित्त के माध्यम से चलनिधि सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ उधार या मीयादी निधि परिचालन की सुविधा दी गई • ऑपरेशन ट्विस्ट सहित आस्ति क्रय • फॉरवर्ड गाइडेंस

नोट: बीपीएस= बेसिस पॉइंट

स्रोत: जीओआई (2021), *आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21*, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.

निवेश में और एक तिहाई आधारभूत संरचना विकास में गया. आगामी वर्षों में पैकेज लागू होने के साथ कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में खुदरा ऋण के संवितरण की स्थिति बेहतर रहने की संभावना है.

1.8 कृषि आधारभूत संरचना पर नए सिरे से बल देना

महामारी ने भविष्य के लिए अनुकूल आधारभूत संरचना तैयार करने की आवश्यकता को पुनः रेखांकित कर दिया है. इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आधारभूत संरचना के लिए वित्तीय वर्ष 2022 में ₹5.5 लाख करोड़ (वित्तीय वर्ष 2021 के बजट से 34.5% अधिक) के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है. वित्तीय वर्ष 2021 की अप्रत्याशित घटनाओं ने आधारभूत संरचनाओं के लिए दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण हेतु पेशेवर रूप से प्रबंधित विकास वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता को रेखांकित किया है ताकि इस प्रकार की संरचनाओं के लिए वित्तपोषण किया जा सके और इन्हें बढ़ावा दिया जा सके.

महामारी ने हमें शांति काल के दौरान कृषि क्षेत्र में फार्म-गेट पर आधारभूत संरचना में निवेश के महत्व की याद दिला दी है ताकि यह संकट के समय उपयोगी सिद्ध हो सके. पर्याप्त भंडारण, कटाई के बाद मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला संयोजन के लिए इस तरह के निवेश की आवश्यकता है. एएनबी पैकेज के तहत फार्म-गेट पर आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए ₹1 लाख करोड़ की राशि से केंद्रीय योजना के रूप में स्थापित कृषि आधारभूत संरचना निधि (एआईएफ) एक गेम चेंजर साबित हो सकती है (बॉक्स 1.3).

वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में भी संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को बढ़ाते हुए मत्स्य पालन और समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर बल

बॉक्स 1.3: कृषि आधारभूत संरचना निधि

कृषि आधारभूत संरचना निधि वित्तीय वर्ष 2021 से वित्तीय वर्ष 2030 के दौरान परिचालन में रहेगी. इसके अंतर्गत कटाई उपरांत प्रबंधन और सामुदायिक कृषि आस्तियों के लिए व्यवहार्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यावधि से दीर्घावधि ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी. इस योजना के अंतर्गत बैंक और वित्तीय संस्थान प्राथमिक कृषि ऋण समितियों; सहकारी विपणन समितियों; कृषक उत्पादक संगठनों; स्वयं सहायता समूहों; संयुक्त देयता समूहों; बहु उद्देश्यीय सहकारी समितियों; कृषि उद्यमियों; स्टार्ट-अप्स; और केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक—निजी साझेदारी परियोजनाओं के लिए ₹2 करोड़ की सीमा तक ऋण उपलब्ध कराएंगे और इसके साथ-साथ अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए 3% वार्षिक दर से ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

कृषि आधारभूत संरचना निधि ₹2 करोड़ तक के ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमी योजना हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं को ऋण गारंटी कवरेज भी प्रदान करती है.

दिया गया है. इसका उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना और किसानों की आय बढ़ाना है.

बजट में 'ऑपरेशन ग्रीन' के दायरे को 3 फसलों (प्याज, टमाटर और आलू) से बढ़ाकर 22 नाशवान पण्यों को शामिल करने के प्रस्ताव से आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता में सुधार होगा, कीमतों में उतार-चढ़ाव कम होगा और कृषि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.

एआईएफ का विस्तार कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के लिए करने और ई-नाम पोर्टल के साथ 1,000 अतिरिक्त एपीएमसी मंडियों के एकीकरण (1,000 मंडियां पहले से ही जुड़ी हैं) से किसानों की बाजार पहुंच बेहतर होगी और विपणन दक्षता को बढ़ावा मिलेगा और यह किसानों के लिए अधिक लाभकारी होगा.

1.9 महामारी के दौरान राजकोषीय दबाव का प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान भारत की राजकोषीय स्थिति को दोहरी मार का सामना करना पड़ा - एक ओर लॉकडाउन के कारण राजस्व में कमी आई और दूसरी ओर महामारी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ा. अन्य देशों के विपरीत भारत ने उभरती स्थिति को ध्यान में रखकर और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए मध्यम आकार के सहायता पैकेज कार्यान्वित किए. अर्थव्यवस्था के धीरे-धीरे खुलने के साथ सरकार ने घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने के लिए व्यय बढ़ाया. वित्तीय वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान व्यय ₹34.5 लाख करोड़ तक पहुँच गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2021 के बजट अनुमान में यह ₹30.4 लाख करोड़ था. यह राजकोषीय घाटा - सकल घरेलू उत्पाद (संशोधित अनुमान) का 9.5% रहा, जिसके लिए सरकारी उधार, बहुपक्षीय उधार, लघु बचत निधि और अल्पावधि उधार के माध्यम से निधि जुटाई गई.

वित्तीय वर्ष 2021 के लिए, राज्यों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% तक की अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति दी गई थी - इसका आधा हिस्सा राज्य स्तर पर लागू सुधारों के कार्यान्वयन के अधीन है.[15]

1.10 आशा के साथ आगे बढ़ते कदम

वित्तीय वर्ष 2021 के समापन के समय महामारी की दूसरी लहर ने भारत के अधिकांश हिस्सों को फिर से ठप कर दिया था. हालांकि, टीकाकरण के लिए जारी अभियान को देखते हुए आशा थी कि मध्यम से लंबी अवधि में वायरस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा. भारत की विकास यात्रा के प्रमुख उत्प्रेरक - निजी निवेश और उपभोग को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें पूर्ण प्राथमिकता के साथ निरंतर कार्य कर रही हैं. इस दिशा में लगातार, सक्रिय, सुविचारित और अपेक्षित नीतिगत समर्थन और सुधारों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है. इसी आशा और अपेक्षा के बल पर नाबार्ड पूरे वित्तीय वर्ष 2021 में सभी सावधानियों के साथ काम करता रहा. महामारी के दौरान कृषि क्षेत्र की अनुकूलता और प्रत्याशा तथा वित्तीय वर्ष 2021 में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराने की हमारी अपनी क्षमता ने हमें भविष्य के लिए विश्वास से भर दिया है.

वित्तीय वर्ष 2021 में नाबार्ड का प्रदर्शन अच्छा रहा है और इस विनाशकारी वर्ष के दौरान बढ़ते रहने का हमारा अनुभव आगामी अध्यायों में उल्लिखित है. इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान हमने आधार स्तर पर कार्यरत ऋण और गैर-ऋण संस्थाओं के सामने उपस्थित समस्याओं पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है और ग्रामीण भारत की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उनके परिचालनों के लिए पूरी सुविधा प्रदान की है. इस प्रक्रिया में हमने यथासंभव अनुदान-आधारित सहयोगों को बढ़ाया और सहकारिता क्षेत्रों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे वित्तीय मध्यस्थों के पात्रता मानदंडों में रियायत दी (या बदल दिया). इस रिपोर्ट में आगे स्पष्ट होगा कि हमारे दृष्टिकोण ने हमारी पुनर्वित्त गतिविधि को विस्तृत और गहन करने में मदद की है. सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान हम चलायमान तो नहीं रहे, लेकिन चुस्त-दुरुस्त बने रहे. नाबार्ड के अध्यक्ष महोदय ने कई राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सौहार्दपूर्ण विचार-विमर्श किए. इस सार्थक पहल के परिणामस्वरूप कई राज्य सरकारों ने नाबार्ड से अधिकाधिक वित्त सुविधा का लाभ उठाया. हमें एक बड़ी सीख यह मिली है कि भौतिक बाधाओं को दूर

करके प्रौद्योगिकी हमारे सहयोगों को बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकती है. कोविड-19 संकट ने हमें एक नए ढंग से सोचने और कार्य करने के लिए बाध्य किया और ग्रामीण भारत को प्रगति पथ पर निरंतर आगे ले जाने की हमारी प्रतिबद्धता को नई दिशा देते हुए बेहतर निर्माण के नए अवसर उपलब्ध कराए.

नोट:

1. संयुक्त राष्ट्र महासचिव (उनके दिनांक 19 मार्च 2020 के भाषण से उद्धृत)
2. जीओआई (2021ए) 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय का अनंतिम अनुमान, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार.
3. आईएमएफ़ (2021), वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन डीसी.
4. विश्व बैंक (2021), ग्लोबल इकॉनोमिक प्रोस्पेक्ट्स (जनवरी 2021), विश्व बैंक, वाशिंगटन डीसी.
5. जीओआई (2021बी), आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
6. जीओआई (2021 ए), नोट 2.
7. जीओआई (2021ए), नोट 2.
8. जीओआई (2021सी), खाद्यान्न उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.
9. जीओआई (2021बी), नोट 5.
10. मत्स्यपालन संबंधी सभी डाटा जीओआई (2021बी) से उद्धृत, नोट 5.
11. पीआईबी (2021), भारत ने 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात में उत्कृष्ट प्रगति दर्ज की गई, पत्र सूचना कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, 10 जून. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1725891.
12. जीओआई (2021बी), नोट 5.
13. बैंकों द्वारा नाबार्ड के एन्श्योर पोर्टल में प्रस्तुत डाटा के अनुसार.
14. डाटा भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के मई के मासिक बुलेटिन आरबीआई (2021) से उद्धृत. यह डाटा अनंतिम है और यह कुछ चयनित बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल गैर-खाद्य ऋण का 90% हिस्सा शामिल है.
15. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 28 राज्यों की निवल उधार सीमा ₹6.4 लाख करोड़ निर्धारित की गई है जो प्रत्येक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3% के राजकोषीय घाटे के अनुरूप है.

अध्याय 1 का परिशिष्ट

कोविड-19 महामारी के दौरान नाबार्ड की पहलें

कोविड-19 महामारी अपने साथ ऐसा भयावह संकट लेकर आई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. इस महामारी ने विश्व की अर्थव्यवस्था को भी क्षत-विक्षत कर दिया है. किन्तु इतिहास गवाह है कि संकट कितना भी गहरा रहा हो, मनुष्य ने अपने हौसले के दम पर हर संकट पर विजय पाई है.

भारत सरकार की ओर से इस महामारी से निपटने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाए गए. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों के अलावा, जरूरतमंदों को तत्काल अल्पावधि आर्थिक राहत उपायों के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीने का मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की गई और भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मध्यावधि और दीर्घावधि पुनरुद्धार तथा सुधार के लिए आत्मनिर्भर भारत 2.0 और 3.0 पैकेज जारी किए गए.

हम सब जानते हैं कि आपदा की स्थिति में लिए जाने वाले निर्णय कभी स्थिर नहीं होते हैं. सुधार की स्थिति और गति के आधार पर उठाए गए कदमों का आकलन करके इनमें अपेक्षित बदलाव करते हुए चरणबद्ध रूप से लागू किया जाता है. ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि ऐसी वर्तमान संस्थाओं और तंत्रों की तत्काल पहचान की जाए जिन्हें सहायता कार्य में लगाया जाना है. इस आलेख में महामारी के दौरान हमारे समक्ष उपस्थित चुनौतियों और इनके निवारण के लिए हमारी ओर से किए गए उपायों का ब्यौरा प्रस्तुत है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाग डालने वाली नाबार्ड की परियोजनाओं और पहलों को भी निम्नलिखित बाधाओं/ समस्याओं का सामना करना पड़ा;

- परियोजना कार्यान्वयनकर्ता स्टाफ और समुदायों के मध्य संचार में बाधा;
- आम जनता और सामग्री की आवाजाही पर प्रतिबंध होने के कारण विलंब; और
- निधि प्रवाह में रुकावट और महामारी से बाधित अर्थव्यवस्था की स्थिति डिजिटल पहुंच की कमी की वजह से अधिक खराब हो गई.

इस बीच ग्रामीण समुदाय निम्नलिखित समस्याओं से ग्रस्त रहे

- ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचना की कमी;
- रोजगार का अचानक खत्म हो जाना, मजबूरीवश मजदूरों का वापस अपने गृह राज्य लौट जाना, भूमि पर बढ़ता दबाव, ग्रामीण आजीविका विकल्पों का अभाव;

- आवश्यक सामग्री की आपूर्ति शृंखला में बाधा; और
- आय में हानि, घटती चुकौती क्षमता.

कई समुदायों ने ज़रूरतमंदों तक पहुंचने, संसाधनों के संग्रहण और लोगों की सहायता के लिए फोन और सोशल मीडिया जैसे प्रौद्योगिकी उपकरणों का सहारा लिया और इनका उपयोग आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, सरकारी प्रयासों में सहभागिता, मास्क और किट तैयार करने तथा वापस लौट रहे मजदूरों की सहायता के लिए किया.

समुदाय आधारित संस्थाएं यथा स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों ने इस सहायता कार्य में बढ़-चढ़ कर भाग लिया. नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबंधकों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने सरकारी एजेंसियों के समन्वय से इन संस्थाओं के माध्यम से उनके सदस्यों के उत्पाद की बिक्री को सुलभ कराया ताकि राज्य सरकार की ओर से सब्जियों और किराना सामग्री की आपूर्ति में सहायता की जा सके.

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने पीएम केयर्स निधि में स्टाफ अंशदान के माध्यम से ₹9 करोड़ के सीधे योगदान के साथ-साथ महामारी से निपटने के लिए बहु-आयामी कदम उठाए.

ऋण संबंधी नीतियों और विनियमों का उदारीकरण

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदत्त विशेष चल निधि और अतिरिक्त विशेष चल निधि से नाबार्ड के अभियान को बल मिला और इसके तहत ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए पुनर्वित्त नीति को उदार बनाकर उन ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान किया गया जो पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं थीं.
- खाद्य प्रसंस्करण निधि के तहत उधारकर्ता निकायों से प्राप्य ₹8.38 करोड़ के मूलधन और ब्याज की अदायगी स्थगित कर दी गई ताकि इन निकायों के लिए ऋण चुकौती का भार कम किया जा सके और व्यापार निरंतरता सुनिश्चित हो सके.
- कोविड-19 संबंधी दबाव के समाधान के लिए संकल्प की रूपरेखा में खाद्य प्रसंस्करण निधि के अंतर्गत उधारकर्ताओं को मूलधन की चुकौती के लिए 18 से 24 महीने (ऋणस्थगन के साथ) का समय विस्तार दिया गया. उधारकर्ताओं को संचित ब्याज के लिए निधिकृत- ब्याज सावधि ऋण मंजूर किए गए.

क्षमता निर्माण और ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना

- नाबार्ड द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहु-सेवा केन्द्रों में परिवर्तित करने, कृषि आधारभूत संरचना पर बल देने और जल, स्वच्छता और आरोग्य से संबंधित परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने की पहलें स्वतः ही महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों में समाहित हो गईं.
- महामारी की वजह से मजदूरों का अपने गृह राज्य में लौटना शुरू होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रभावी जिलों में फिर से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण देने हेतु आबंटन बढ़ाया गया. इसके तहत सर्वाधिक प्रभावित राज्यों - असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 744 सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रमों, 500 आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन किया गया.

आपदा का सामना करने की तैयारी हेतु निवेश

आधारभूत संरचना

एक सुदृढ़ सुविकसित आधारभूत संरचना महामारी जैसी आपदाओं के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होती है. अच्छी सड़क कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और सामाजिक सुविधाओं तक पहुंच, पेयजल, आरोग्य और स्वच्छता संबंधी आधारभूत संरचना विकसित करने और निधि संवितरण में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को प्रदत्त सहायता उपायों का ब्यौरा चित्र अ 1.1 में दिया गया है.

वित्तीय समावेशन

महामारी के कारण ग्रामीण महिलाओं के लिए घर पर ही नकद भुगतान, आजीविका, नकद सब्सिडी जैसे सहयोग आवश्यक हो गए थे. हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के शुरू होने से बैंकिंग तक पहुंच बनाना और इसका उपयोग करना सुगम हुआ है जिससे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और ऑनलाइन व्यवसाय को बढ़ावा मिला है. अधिकांश ग्रामीण नागरिक सभी प्रौद्योगिकी समाधानों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसलिए नाबार्ड ने भविष्य की आपदाओं के लिए डिजिटल-वित्तीय तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया.

- नाबार्ड ने बैंकों को भारत बिल पेमेंट सिस्टम में ऑन-बोर्डिंग के लिए सहयोग किया ताकि बैंक अपने ग्रामीण ग्राहकों को ऑनलाइन यूटिलिटी भुगतान सेवाएँ प्रदान कर सकें.
- 148 मोबाइल डेमो वैन [वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) के तहत] के माध्यम से प्रौद्योगिकी आधारित डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में 3.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए.
- नाबार्ड ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कार्यान्वयन में भी मदद की जिसके माध्यम से 108 ग्रामीण सहकारी बैंकों में 10.7 लाख महिलाओं के जन धन खातों में सीधे नकद राशि का अंतरण किया जा सका.
- नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से आग्रह किया कि वे महामारी के दौरान कठिनाइयों का सामना करने वाले बैंकिंग करेस्पोंडेंट से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें और उन्हें तीन महीने के लिए स्वास्थ्य सेवा, बीमा कवर, कार्य-निष्पादन आधारित पारिश्रमिक प्रदान करें.

चित्र अ 1.1: महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए आधारभूत संरचना विकास

राज्य-वार आबंटन के लिए संशोधित मानदंड	ग्रामीण गरीबी और प्रति व्यक्ति प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रवाह को मानदंड के रूप में जोड़ा गया.
आईएससी के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन को बढ़ाना	परियोजनाओं की मंज़ूरी में तेजी लाई गई.
आरआईडीएफ़ के अंतर्गत अनाहरित बकाया शेष तक सुरक्षित पहुँच	चालू (ऑन-गोइंग) आरआईडीएफ़ खेपों के अंतर्गत आरआईडीएफ़ की बंद खेपों की बकाया राशि का उपयोग करके अधिक से अधिक परियोजनाओं की मंज़ूरी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया गया.
आरआईडीएफ़ परियोजनाओं की समय-सीमा बढ़ाई गई	आरआईडीएफ़ के अंतर्गत मंज़ूर परियोजनाओं के प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी मंज़ूरी के लिए समय-सीमा बढ़ाई गई
आरआईडीएफ़ XX और XXI परियोजनाओं का विस्तार किया गया	खेप XX और XXI के अंतर्गत परियोजनाओं की फ़ेजिंग को बढ़ाया गया ताकि इन्हें पूरा करने के लिए और अधिक समय मिल सके.
आरआईडीएफ़ और एमआईएफ़ की समूह निधि में वृद्धि	केंद्रीय बजट (वित्तीय वर्ष 2022) में आधारभूत संरचना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आरआईडीएफ़ की समूह निधि को बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ किया गया और एमआईएफ़ को दोगुना करके ₹10,000 करोड़ कर दिया गया.
डिजिटलीकृत आरआईडीएफ़ अभिलेख	आरआईडीएफ परियोजनाओं की दूरस्थ निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिससे भौतिक संपर्क को कम करने में मदद मिली

नोट: आईएससी=आंतरिक मंज़ूरी समिति; एमआईएफ़= सूक्ष्म-सिंचाई निधि; आरबीआई= भारतीय रिजर्व बैंक; आरआईडीएफ़= ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि

चित्र अ 1.2: संकट का सामना करने की तैयारी के लिए वित्तीय समावेशन में सुधार के उपाय

- बैंकिंग लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो एटीएम का उपयोग
- माइक्रो एटीएम के माध्यम से रूपे-कार्ड सक्रिय करने के लिए ग्रीन पिन
- डेमो मोबाइल वैन के माध्यम से वित्तीय साक्षरता जागरूकता बढ़ाना
- दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले वी सैट और मोबाइल सिग्नल बूस्टर लगाना

जागरूकता का प्रसार

- बैंक शाखाओं में भीड़ कम करने और ग्रामीण लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा की गई.
- नाबार्ड ने मोबाइल डेमो वैन, माइक्रो-एटीएम, पॉइंट ऑफ़ सेल डिवाइस और मोबाइल पॉइंट ऑफ़ सेल ऐप के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग के उपयोग के बारे में क्षेत्रीय भाषाओं में 14 शैक्षणिक फिल्में बनाईं.
- एफआईएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर जागरूकता बढ़ाने और बेहतर तरीके से सीखने की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए गेम्स जैसे माइक्रो-मॉड्यूल बनाए गए. ये माइक्रो-मॉड्यूल मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हैं और उपयोगकर्ता इसका इस्तेमाल कभी भी-कहीं भी कर सकते हैं.
- स्वयं सहायता समूहों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी से संबंधित 40 लाख संदेश भेजने के लिए नाबार्ड के ई-शक्ति पोर्टल का उपयोग किया गया.
- नाबार्ड ने अपनी वेबसाइट पर कोविड-19 एडवायजरी के लिए एक समर्पित पेज तैयार करने के अलावा, महामारी के दौरान व्यापार और संचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई उत्पाद जारी किए. इनमें महामारी के दौरान 'सुरक्षित बैंकिंग' पर बनाई गई एक एनीमेशन फिल्म और महामारी का सामना करने में नाबार्ड के सहयोग विषय पर एक फिल्म और पुस्तिका शामिल है.